हर इंसान-एक समान
एक राष्ट्र-एक जान
मेरा भारत महान

अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ
समता आन्दोलन समिति (रजि.)

प्रान्तीय कार्यालय :जी-3, संगम रेजीडेन्सी, प्लाट नं. 9-10, गंगाराम की ढाणी, वैशाली नगर, जयपुर
Website:www.samtaandolan.in Email :samtaandolan@yahoo.in

पाराशर नारायण प्रदेश अध्यक्ष (पदेन संरक्षक)
रामनिरंजन प्रदेश महासचिव (पदेन संरक्षक)
ललित चाचाण प्रदेश कोषाध्यक्ष (पदेन संरक्षक)

श्री राम नारायण धाणका
संरक्षक
मो. 9829069242

कालू लाल भील
प्रदेशाध्यक्ष
मो. 7726914880

डॉ. नारायण लाल निनामा
महासचिव
मो. 9982556464

लक्ष्मीनारायण धाणका
महासचिव
मो. 9950750063

प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं पदेन सम्भागीय अध्यक्ष

अजमेर :
आनन्दी लाल डाबी
मो. 9414212600

बीकानेर :
मदन लाल भील
मो. 9829020737

भरतपुर :
रामजी लाल कोली
मो. 9414689980

जयपुर :
रतन कुमार सिंह धाणका
मो. 9413609242

जोधपुर :
सुखदेव भील
मो. 9928341925

कोटा :
हरिशंकर भील
मो. 9928746005

उदयपुर:
सुरेश लक्खा
मो. 9602319177

क्रमांक 15130 - 15922 दिनांक : 02.07.2020

श्रीमान रामनाथ कोविंद साहेब	श्रीमान एस.ए.बोबडे	श्रीमान नरेन्द्र मोदी साहेब
महामहिम राष्ट्रपति	माननीय मुख्य न्यायाधीश	माननीय प्रधानमंत्री महोदय
भारत सरकार	सर्वोच्च न्यायालय,	भारत सरकार
नई दिल्ली।	नई दिल्ली।	नई दिल्ली ।

विषयः—राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के चेयरमेन पद पर किसी असली जनजाति के व्यक्ति को ही नियुक्ति देने बाबत।
संदर्भः— श्री किरोडी लाल मीणा (फर्जी एसटी) भाजपा सांसद को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग चेयरमेन बनाने की खबरें।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि हमें राजस्थान राज्य के अखबारों में छपी खबरों से यह ज्ञात हुआ है कि राजस्थान से राज्यसभा के सांसद बने श्री किरोडी लाल मीणा को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष बनाये जाने की चर्चायें चल रही हैं। हम आपकी जानकारी में यह लाना चाहते हैं कि :—

1. राजस्थान में मीणा जाति अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं है। केन्द्र सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के पत्र संख्या 11030/01/2013—सी एण्ड एल एम—। दिनांक 26.08.2013 की प्रति संलग्न है।

2. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रधानपीठ जोधपुर द्वारा दिनांक 18.02.2014 को आदेश दिया गया है कि मीणा समुदाय को अनुसूचित जनजाति का कोई लाभ नहीं दिया जाये। आदेश की प्रति संलग्न है। "मीणा" समुदाय के बहुत से लोग अब अविधिक तरीके से "मीना" लिखने लग गये है।

3. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका संख्या 21685/2013, 14722/2015, 12789/2014, 14221/2014, 10493/2015, 13978/2013, 6449/2014 अर्थात कुल 07 याचिकाएँ लम्बित हैं, जिनमें मीणा समुदाय को अनुसूचित जनजाति का लाभ नहीं देने की प्रार्थनाएँ की गई हैं। दुर्भाग्य से राजस्थान सरकार धनाढ्य,सम्पन्न, सशक्त मीणा समुदाय के दवाब में राजस्थान उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश दिनांक 18.02.2014 की पालना नहीं कर पा रही है और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशगण उपरोक्त लम्बित याचिकाओं का निस्तारण नहीं कर पा रहे हैं।

4. मीणा समुदाय धनाढ्य, सम्पन्न, सशक्त, राजशाही और जमींदारा समुदाय है। अतः स्वभाविक रूप से अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चलाई जा रही सरकारी योजनाओं और आरक्षित पदों का बड़ा भाग तथा राजस्थान राज्य में लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा अविधिक रूप से हड़पता चला आ रहा है। राजस्थान राज्य के लगभग 55 लाख असली जनजाति के लोग सभी सरकारी योजनाओं एवं आरक्षण के लाभ से वंचित रहने के कारण अत्यन्त दयनीय एवं विपन्न जीवन जीने को मजबूर हैं।

TRNhanka

(लगातार---- 2)

एक राष्ट्र-एक जान

मेरा भारत महा

अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ

समता आन्दोलन समिति (रजि.)

प्रान्तीय कार्यालय :जी-3, संगम रेजीडेन्सी, प्लाट नं. 9-10, गंगाराम की ढाणी, वैशाली नगर, जयपुर

Website:www.samtaandolan.in Email :samtaandolan@yahoo.in

पाराशर नारायण
प्रदेश अध्यक्ष (पदेन संरक्षक)

रामनिरंजन
प्रदेश महासचिव (पदेन संरक्षक)

ललित चाचाण
प्रदेश कोषाध्यक्ष (पदेन संरक्षक)

श्री राम नारायण धाणका
संरक्षक
मो. 9829069242

कालू लाल भील
प्रदेशाध्यक्ष
मो. 7726914880

डॉ. नारायण लाल निनामा
महासचिव
मो. 9982556464

लक्ष्मीनारायण धाणका
महासचिव
मो. 9950750063

प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं पदेन सम्भागीय अध्यक्ष

अजमेर :
आनन्दी लाल डाबी
मो. 9414212600

बीकानेर :
मदन लाल भील
मो. 9829020737

भरतपुर :
रामजी लाल कोली
मो. 9414689980

जयपुर :
रतन कुमार सिंह घाणका
मो. 9413609242

जोधपुर :
सुखदेव भील
मो. 9928341925

कोटा :
हरिशंकर भील
मो. 9928746005

उदयपुर:
सुरेश लक्खा
मो. 9602319177

क्रमांक

दिनांक :

उपरोक्त परिस्थितियों के मद्देनजर यदि श्री किरोड़ी लाल मीणा को या मीणा समुद के अन्य किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष या सदस्य बना जाता है तो वह पूरे देश के 10 करोड़ असली जनजाति नागरिकों के साथ अन्याय ए विश्वासघात होगा। अतः आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि:–

1. फर्जी मीणा जनजाति के श्री किरोड़ी लाल मीणा को या अन्य किसी व्यक्ति को राष्ट्री अनुसूचित जनजाति आयोगका अध्यक्ष या सदस्य नहीं बनाया जाये तथा सरकार योजनाओं व जनजाति आरक्षण का कोई लाभ नहीं दिया जाये। किसी असली जनजाति के सामाजिक नेता को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष या सदस्य बनाय जाये।

2. राजस्थान उच्च न्यायालय को वर्षों से लम्बित उपरोक्त याचिका संख्या 21685/2013, 14722/2015, 12789/2014, 14221/2014, 10493/2015, 13978/2013, 6449/2014 का तत्काल निस्तारण करने के लिए न्यायोचित निर्देश प्रदान किये जायें। ताकि पूरे देश के 10 करोड़ असली आदिवासियों तथा राजस्थान राज्य के 55 लाख से अधिक असली आदिवासियों को सरकारी योजनाओं और आरक्षण का लाभ मिल सके, उनका पिछड़ापन दूर हो सके।

चूंकि फर्जी मीणा जनजाति के लोगों द्वारा पूरे देश के करोड़ों असली आदिवासियों का हक 70 वर्षों से लूटा जा रहा है इसलिए आदिवासियों में सरकारी तंत्र के खिलाफ आकोश बढता जा रहा है। बहुत से लोग नक्सलवाद की ओर अग्रसर हो रहे हैं। यदि फर्जी मीणा जनजाति के लोगों को असली जनजाति के हकों को लूटने से तत्काल नहीं रोका गया तो कभी भी बड़े पैमाने पर उपद्रव फैल सकता है।

सादर,

भवदीय,

[signature]

राम नारायण धाणका
संरक्षक

प्रतिलिपिः– माननीय लोकसभा/राज्यसभा सांसदों को सादर सूचनार्थ एवं असली जनजाति की भलाई के लिए यथोचित कार्यवाही करने हेतु प्रेषित है।

[signature]

राम नारायण धाणका
संरक्षक

F.No. 11030/01/2013-C&LM-I
Government of India
Ministry of Tribal Affairs
C&LM Division
******

Shastri Bhawan, New Delhi
Dated: 26th August, 2013

To,
Shri Ratan Kumar,
Plot No. 21 Shubham Vihar,
(Kajod Colony), Mahesh Nagar,
Jaipur- 302015,
Rajasthan.

Subject: **Furnishing of Information under RTI Act, 2005.**

Sir,

Plaese refer to your application dated 15.3.2013 transferred by the Department of Social Justice & Empowerment vide its O.M. No. 17020/3/2013-SCD (RL Cell) dated 10.7.2013.

It is to inform you that the "Meena" 'मीणा' community has not been included in the list of Scheduled Tribes in Rajasthan. However, a copy of relevant part of Scheduled Caste and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976 (No. 108 of 1976) in relation to the State of Rajasthan, is enclosed.

Yours faithfully,

Purnima
26/8-13
(Purnima Tudu)
Under Secretary & CPIO
Tel. 23074408

[NB. In terms of Section 19 (1) of the Right of Information Act, 2005, Shri Rajeev Prakash, Director, in the Ministry of Tribal Affairs (Room No. 722 "A" Wing, Shastri Bhawan, New Delhi- 110001; Tel. No. 23073176 (Office) has been designated as Appellate Authority for the Ministry of Tribal Affairs for the purpose of the implementation of the Right to Information Act, 2005].

Copy to: (i) Shri R.P. Puri, Under Secretary & CPIO, Ministry of Social Justice & Empowerment, Shastri Bhawan New Delhi w.r.t. their O.M. No. 17020/03/2013-SCD- (RL Cell) dated 10.7.2013.

(ii) U.S. (PC&V) w.r.t. their Dy No. 205 dated 12.7.2013.

No.11030/01/2013 - C&LM-I
Speed Post
SPEED POST
Shri Ratan Kumar
Plot No.21 Shubham Vihar
Jaipur-302015
Rajasthan.

EMS SPEED POST
ED 09047801 2IN

(89)

Annx C-11

Certified P.S. Copy of order dt 18/2/14.

Anx-11

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT

JODHPUR

S.B. CIVIL WRIT PETITION NO. 13978/2013

Sugan Lal Bhil S/o Shri Nand Lal Bhil, Age 35 years, R/o Mukam Post Raita, Panchayat Samiti Begu, District Chittorgarh.

...PETITIONER

VERSUS

1. State of Rajasthan through Additional Chief Secretary, Rural Development & Panchayati Raj Department, Government Secretariat, Jaipur.

2. Principal Secretary, Department of Personnel, Government of Rajasthan, Secretariat, Jaipur.

3. Director, Elementary Education, Bikaner.

4. Chief Executive Officer, Zila Parishad, Chittorgarh.

5. Shri Ganpath Lal Meena S/o Shri Narayan Lal Meena, R/o Shri Narayan Lal Meena, R/o Gram Pachundal, Post Shadi, District Chittorgarh-3012022.

6. Shri Kunj Bihari Meena S/o Shri Hari Om Meena, R/o Dheebri Kali Sindh, Post Jaloda Khatiya, Tehsil Peepalda, District Kota-325214.

सही प्रतिलिपि
19 FEB 2014
प्रशासनिक अधिकारी न्यायिक
राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

OATH COMMISSIONER
REVENUE, CRIMINAL, CIVIL
RAJ. HIGH COURT, JODHPUR

(90) 8

7. Shri Meghram Meena S/o Shivji Ram Meena, R/o Village Birodha, Post Bhanakpura, Tehsil Mahuwa, District Dausa-321610.

...RESPONDENTS

S. B. CIVIL WRIT PETITION UNDER ARTICLE 226 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

AND

IN THE MATTER OF APPOINTMENT ON THE POST OF TEACHER GRADE III

AND

IN THE MATTER OF ADVERTISMENT DATED 24.2.2012 FOR APPOINTMENT ON THE POST OF TEACHER GRADE III

AND

IN THE MATTER OF NON-COMPLIANCE OF THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA

To,

सत्य प्रतिलिपि
19 FEB 2014
प्रशासनिक अधिकारी न्यायिक
राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

91

S.B. Civil Writ Petition No.13978/2013.

DATE OF ORDER : February 18, 2014

PRESENT

Hon'ble Mr. Justice Gopal Krishan Vyas

Mr. Manjul Shrimali for the petitioner.
Mr. K.L. Thakur, Addl. Advocate General.

BY THE COURT :

In this case, after hearing learned counsel for the petitioner, Mr. K.L. Thakur, Addl. Advocate General is directed to accept notice. Let copy be supplied to him.

In this writ petition, the petitioner who belongs to "Bhil" caste of Scheduled Tribe community has prayed for direction to declare all the certificates issued to the candidates or any other person belonging to "Meena" community beyond the purview of notification dated 20.09.1976 in which caste of Scheduled Tribes are published and they shall not be permitted to seek appointment under the category of Scheduled Tribe for any post in the State including Teacher Grade-III. Further, it is prayed that appointment orders qua the Scheduled Tribe category passed in favour of the candidates possessing certificate of "Meena" community may be quashed and set aside.

सच्ची प्रतिलिपि
19 FEB 2014
प्रशासनिक अधिकारी न्यायिक
राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

Learned counsel for the petitioner submits that under the Constitution of India reservation for Scheduled Caste and Scheduled Tribe is provided and, for that purpose, notification has been issued by the Union of India vide notification dated 20.09.1976 which is placed on record as

Annex.-9. In the said notification, in Part XIII, the castes of Scheduled Tribe of Rajasthan are enumerated. In item No.2 "Bheel-mina" and in item No.9, word "mina" is included. No word "meena" is used. Therefore, the issuance of certificate to the caste of "meena" is contrary to notification issued on 20.09.1976.

Learned counsel for the petitioner submits that under the Right to Information Act, an application was sent by one Ratan Kumar to the Government of India, Ministry of Tribal Areas and, in response to that, an information was given under the Right to Information Act, 2005 that "meena" (मीणा) community has not been included in the list of Scheduled Tribe in Rajasthan. Therefore, if the caste "meena" (मीणा) is not included in the notification dated 20.09.1976, then, obviously all the certificates issued to the candidates of "meena (मीणा)" community are illegal and contrary to the notification issued by the Central Government.

सही प्रतिलिपि
19 FEB 2014
प्रशासनिक अधिकारी न्यायिक
राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

Learned counsel for the petitioner submits that the State Government may be directed to issue directions to all the authorities of the State that no certificate of Scheduled Tribe category shall be issued to the candidates belonging to the "meena (मीणा)" community and it may be notified that all the certificates earlier issued to members of the "meena (मीणा)" community shall be treated null and void.

Shri K.L. Thakur, learned Addl. Advocate General appearing on behalf of the respondents, submits that directions as prayed by the petitioner cannot be given without clarification from the State Government, therefore,

93

this writ petition may be dismissed.

After hearing learned counsel for the parties, I am of the opinion that there is right of reservation in employment created under the Constitution in favour of the members of the ST/SC category of the State. For the same notifications have been issued and for the Scheduled Tribes of Rajasthan, notification Annex.-9 dated 20.09.1976 is issued in which following castes are included in the list of Scheduled Tribes in Part XIII, which reads as under :

"PART XIII.-Rajasthan

1. Bhil, Bhil Garasia, Dholi Bhil, Dungri Bhil, Dungri Garasia, Mewasi Bhil, Rawal Bhil, Tadvi Bhil, Bhagalia, Bhilala, Pawra, Vasava, Vasave.

2. Bhil Mina

3. Damor, Damaria

4. Dhanka, Tadvi, Tetaria, Valvi

5. Garasia (excluding Rajput Garasia)

6. Kathodi, Katkari, Dhor Kathodi, Dhor Katkari, Son Kathodi, Son Katkari.

7. Kokna, Kokni, Kukna

8. Koli Dhor, Tokre Koli, Kolcha, Kolgha

9. Mina

10. Naikda, Nayaka, Cholivala Nayaka, Kapadia Nayaka, Mota Nayaka, Nana Nayaka

सही प्रतिलिपि
19 FEB 2014
प्रशासनिक अधिकारी न्यायिक
राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

(94)

11. Patelia

12. Seharia, Sehria, Sahariya."

In the aforesaid Part XIII, obviously the word "mina" is used. The word "meena" is not used. Likewise in the Hindi version also, the following list is included in Part XIII for Rajasthan, which reads as under :

"**1.** भील, भील गरासिया, धोली भील, डुंगरी भील, डुंगरी गरासिया, मेवासी भील, रावल भील, तडवी भील, भगालिया, भलला, पावरा वसवा, वसावे

2. भील मीना
3. डामोर, डामरिया
4. धाणका, तड़वी, तेतारिया, वलवी
5. गरासिया (राजपूत गरासिया से भिन्न)
6. काथोडी, कातकरी, ढोर काथोडी, ढोर कातकरी, सोन काथोडी, सोन कातकरी
7. कोकना, कोकनो, कुकणा
8. कोली,ढोर, टोकरे कोली फोलचा, कोलघा
9. मीना
10. नायकडा, नायक, चोलिवाला नायक, कपाडिया नायक, मोटा नायक, नाना नायक
11. पटेलिया

सेहारिया, सेहरिया, सहारिया"

I have also perused communication dated 26.08.2013 (Annex.-12) in which the Under Secretary & CPIO of the Ministry of Tribal Areas, Government of India gave following information for non-inclusion of "meena (मीणा)" community, which reads as under :

सही प्रतिलिपि
19 FEB 2014
प्रशासनिक अधिकारी न्यायिक
राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

"Subject Furnishing of Information under RTI Act, 2005
Sir,

Please refer to your application dated 15.3.2013 transferred by the Department of Social Justice & Empowerment vide its O.M. No.17020/3/2013-SCD (RL Cell) dated 10.7.2013.

It is to inform you that the "meena" मीणा" community has not been included in the list of Scheduled Tribes in Rajasthan. However, a copy of relevant part of Scheduled Caste and Scheduled

95

Tribes Orders (Amendment) Act, 1976 (No.108 of 1976) in relation to the State of Rajasthan is enclosed.

Yours faithfully,

Sd/-

Under Secretary & CPIO"

In view of the above, apparently it appears that certificate of ST can be issued to caste of "mina" (मीना) but, for the said purpose, the clarification is to be made by the State Government.

Therefore, copy of this order may be sent to the Chief Secretary, Government of Rajasthan, Jaipur with direction to examine the matter and issue necessary directions within a period of one month from the date of receiving certified copy of this order. Copy of this order may be supplied along with photo-stat copy of communication dated 26.08.2013 (Annex.-12) to the Add. Advocate General to communicate the same to the Chief Secretary of the Government of Rajasthan. The Deputy Registrar (Judl.) of this Court is directed to send copy of this order along with copy of letter dated 26.08.2013 (Annex.-12) directly to the Chief Secretary, Government of Rajasthan, Jaipur for compliance.

List this matter for compliance and report to this Court on 05.04.2014.

(Gopal Krishan Vyas) J.

Ojha, a.

सही प्रतिलिपि

2 8 FEB 2014

अनुभाग अधिकारी न्यायिक
राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

P.T.O.